

Partnership results from a contract and is governed by the Partnership Act 1932. The partnership is also governed by the general provision of the Indian Contract Act on such matters where the Partnership Act is silent. It is expressly mentioned that the provision of India Contract Act which is not repealed will be applicable on Partnership until and unless such provision is in contrary to any provision of Partnership Act, 1932. The rules of contract regarding the capacity to contract, offer, acceptance etc will also be applicable to the partnership. But the rules regarding the status of minor will be governed by the Partnership Act, 1932 since **Section 30** of the Act talks about the position of the minor.

साझेदारी (Partnership):

साझेदारी एक अनुबंध (contract) से उत्पन्न होती है और यह भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 द्वारा नियंत्रित होती है। साझेदारी उन मामलों में, जहाँ साझेदारी अधिनियम मौन (silent) है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के सामान्य प्रावधानों द्वारा भी संचालित होती है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के वे प्रावधान, जिन्हें निरस्त (repeal) नहीं किया गया है, साझेदारी पर लागू होंगे, बशर्ते कि वे साझेदारी अधिनियम, 1932 के किसी प्रावधान के विपरीत न हों। अनुबंध के नियम, जैसे—संविदा करने की क्षमता (capacity to contract), प्रस्ताव (offer), स्वीकृति (acceptance) आदि भी साझेदारी पर लागू होते हैं। किन्तु नाबालिग (minor) की स्थिति से संबंधित नियम धारा 30 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, क्योंकि यह धारा विशेष रूप से नाबालिग की स्थिति का वर्णन करती है।

Nature of Business

It is a business organization where two or more persons agreed to join together to carry out the business for the purpose of earning the profits. It is an extension of a sole proprietorship. It is better than sole proprietorship because in sole proprietorship the business is carried out by the individual with limited capital and limited skill. Due to the limited resources of a single individual carrying a sole proprietorship, a larger business requiring more resources and investment than available to the sole proprietor cannot be thought of such business. On the other hand in partnership, a number of partners join together with their capital to form an agreement and carry out a business jointly.

व्यवसाय की प्रकृति (Nature of Business):

यह एक व्यावसायिक संगठन है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ (profit) कमाने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर व्यापार करने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी (Partnership) को एकल स्वामित्व (sole proprietorship) का विस्तारित रूप (extension) माना जाता है। यह एकल स्वामित्व से बेहतर होती है, क्योंकि एकल स्वामित्व में व्यवसाय एक ही व्यक्ति द्वारा सीमित पूँजी (limited capital) और सीमित कौशल (limited skill) के साथ संचालित किया जाता है।

एक व्यक्ति के सीमित संसाधनों के कारण, ऐसा बड़ा व्यवसाय करना संभव नहीं होता, जिसमें अधिक पूँजी और निवेश की आवश्यकता हो। इसके विपरीत, साझेदारी में कई साझेदार (partners) अपनी-अपनी पूँजी और संसाधनों को मिलाकर एक समझौता (agreement) करते हैं और संयुक्त रूप से व्यवसाय का संचालन करते हैं।

Meaning According to Section 4 of the Partnership Act, 1932

“Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all”.

धारा 4 के अनुसार—
“साझेदारी (Partnership) उन व्यक्तियों के बीच संबंध है, जिन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वे उस व्यवसाय के लाभ को आपस में बाँटेंगे, जो उन सभी द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा, सभी की ओर से संचालित किया जाता है।”

Essential requirements of a partnership

- It must be an association of two or more persons.
- There must exist an agreement between the partners.
- There must be a business undertaking or a commercial activity that is lawful.
- The motive must be to earn the profit and share between the partners.
- The agreement must be to carry out the business jointly or by any of them acting on the behalf of all i.e., there must be mutual agency.

Examples:

A and B buy 100 tons of oil which they agree to sell for their joint account. This forms a partnership and A and B are considered as partners.

A and B buy 100 tons of oil and agreed to share it among them. It does not form a partnership as they had no intention to carry out business.

साझेदारी के आवश्यक तत्व (Essential Requirements of a Partnership):

- यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ (association) होना चाहिए।
- साझेदारों के बीच एक समझौता (agreement) होना आवश्यक है।
- कोई वैध व्यवसाय (lawful business) या वाणिज्यिक गतिविधि (commercial activity) होना चाहिए।
- उद्देश्य लाभ कमाना (profit earning) और उसे साझेदारों के बीच बाँटना होना चाहिए।

- समझौता इस प्रकार का होना चाहिए कि व्यवसाय सभी द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा, सभी की ओर से संचालित किया जाए, अर्थात् पारस्परिक अभिकरण (mutual agency) होना आवश्यक है।

उदाहरण (Examples):

- A और B 100 टन तेल खरीदते हैं और इसे अपने संयुक्त खाते (joint account) के लिए बेचने पर सहमत होते हैं। यह साझेदारी बनाता है और A तथा B साझेदार (partners) माने जाते हैं।
- A और B 100 टन तेल खरीदते हैं और उसे आपस में बाँटने पर सहमत होते हैं। यह साझेदारी नहीं बनाता, क्योंकि उनका व्यवसाय करने का कोई इरादा नहीं था।

Number of members

Any two or more persons may form a partnership. There is no limit imposed on the minimum and the maximum number of partners under the Partnership Act, 1932. According to Companies Act 2013, the maximum number of 100 must not exceed in case of partnership and minimum is 2 partners.

If in any case, it exceeds the maximum limit then it will amount to the illegal association under [Section 464](#) of Companies Act, 2013. According to [Section 11](#) of Companies Act the maximum number of partner in case of:

- Banking purpose-10 persons
- Other purposes- 20 persons
- **सदस्यों की संख्या (Number of Members):**

कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी (partnership) बना सकते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या पर कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- किन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और न्यूनतम 2 साझेदार होना आवश्यक है।
- यदि किसी स्थिति में साझेदारों की संख्या निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है, तो यह धारा 464 के अंतर्गत अवैध संघ (illegal association) माना जाएगा।
- पूर्व में धारा 11 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या—
 - बैंकिंग कार्य (Banking purpose) के लिए – 10 व्यक्ति
 - अन्य कार्यों (Other purposes) के लिए – 20 व्यक्ति निर्धारित थी।

Agreement

The partnership is an agreement in which two or more person has decided to carry out business and share the profit and losses equally. To create a legal relationship it is necessary to form a partnership agreement.

The partnership agreement becomes the foundation or the basis on which it is based. It can be either written or oral. The written agreement is known as a partnership deed. Partnership deed mainly consists of the following details:

- Name and address of its firm and business
- Name and address of its partner
- Capital contributed by each partner
- Profit and loss sharing ratio
- Rate of interest on capital, loan, drawings etc
- Rights, duties and obligation of partners
- Settlement of accounts on the dissolution of the firm
- Salaries, commission payable to partners
- Rules to be followed in case of admission, retirement and death of a partner
- Mode of settlement on disputes among partner.
- Any other affecting the rights of the partners
- **समझौता (Agreement):**
साझेदारी एक ऐसा समझौता (agreement) है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय करने तथा उसके लाभ और हानि (profit and loss) को आपस में बाँटने के लिए सहमत होते हैं। एक विधिक संबंध (legal relationship) स्थापित करने के लिए साझेदारी समझौता करना आवश्यक है।
- साझेदारी समझौता ही उसका आधार (foundation) होता है। यह लिखित (written) या मौखिक (oral) दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित समझौते को “साझेदारी विलेख” (Partnership Deed) कहा जाता है।
- **साझेदारी विलेख (Partnership Deed) में मुख्यतः निम्नलिखित विवरण होते हैं—**
 - फर्म (Firm) और व्यवसाय का नाम व पता
 - साझेदारों (Partners) के नाम और पते
 - प्रत्येक साझेदार द्वारा दिया गया पूँजी (capital)
 - लाभ और हानि बाँटने का अनुपात (profit and loss sharing ratio)
 - पूँजी, ऋण (loan), आहरण (drawings) आदि पर ब्याज की दर (rate of interest)
 - साझेदारों के अधिकार (rights), कर्तव्य (duties) और दायित्व (obligations)

- फर्म के विघटन (dissolution) पर खातों का निपटान (settlement of accounts)
- साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन (salary) या कमीशन (commission)
- साझेदार के प्रवेश (admission), सेवानिवृत्ति (retirement) और मृत्यु (death) की स्थिति में अपनाए जाने वाले नियम
- साझेदारों के बीच विवाद (disputes) के निपटान की विधि (mode of settlement)
- साझेदारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले अन्य प्रावधान (any other terms affecting rights of partners)

Business (Section 12)

The partnership must be created for the purpose of carrying the business which is legal in nature. Co-ownership of property does not amount to the partnership. As per the definition given in Section 2(b), a business includes any trade, occupation or profession. It is any kind of occupation that is not something done just for pleasure. It is an operation conducted by a particular method that is continuous, and from which income or profits can be derived.

व्यवसाय (Business) – धारा 12:

साझेदारी का गठन ऐसे व्यवसाय (business) को संचालित करने के उद्देश्य से होना चाहिए, जो विधिसम्मत (legal) हो। केवल संपत्ति का सह-स्वामित्व (co-ownership) साझेदारी नहीं माना जाता।

धारा 2(b) के अनुसार, “व्यवसाय” में कोई भी व्यापार (trade), व्यवसाय (occupation) या पेशा (profession) सम्मिलित होता है। यह ऐसा कार्य है, जो केवल मनोरंजन (pleasure) के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एक नियमित (continuous) तरीके से संचालित होता है और जिससे आय (income) या लाभ (profit) प्राप्त किया जा सकता है।

Mutual agency (Section 13)

The business is to be carried by all of them or by any one of them on behalf of all. It gives two assumptions

Each partner is entitled to carry out the business. The mutual agency exists between the partners. Each partner is a principal as well as an agent for the other partners. He is bound by the acts of other partners as well as can bind others by his own act.

पारस्परिक अभिकरण (Mutual Agency) – धारा 13:

साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा, सभी की ओर से संचालित किया जाता है। इससे दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं—

- प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय संचालित करने का अधिकार होता है।
- साझेदारों के बीच पारस्परिक अभिकरण (mutual agency) विद्यमान होता है।

प्रत्येक साझेदार, अन्य साझेदारों के लिए एक साथ प्रधान (principal) भी होता है और अभिकर्ता (agent) भी। वह अन्य साझेदारों के कार्यों से बंधा होता है, और अपने कार्यों द्वारा अन्य साझेदारों को भी बाध्य कर सकता है।

Sharing of profit

The agreement is to share profit and losses among the partners. The sharing of profit and losses can be according to the ratio of the capital contributed or equally.

It helps to distribute the burden among the partners in the case when the partnership suffers losses.

लाभ का बंटवारा (Sharing of Profit):

साझेदारी में यह समझौता होता है कि साझेदार आपस में लाभ (profit) और हानि (loss) को बाँटेंगे। लाभ और हानि का बंटवारा पूँजी (capital) के अनुपात में या समान रूप से (equally) किया जा सकता है।

यह व्यवस्था उस स्थिति में साझेदारों के बीच भार (burden) को बाँटने में सहायक होती है, जब साझेदारी को हानि (loss) होती है।

Liability of partnership

All the partners are jointly liable for paying the debts of the firm. The liability is unlimited which means that the partner's private assets can be disposed of for the purpose of paying the debts of the firm.

साझेदारी की देयता (Liability of Partnership):

सभी साझेदार फर्म के ऋणों (debts) के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी (jointly liable) होते हैं।

साझेदारी में देयता असीमित (unlimited) होती है, अर्थात् फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए साझेदारों की निजी संपत्ति (private assets) का भी उपयोग किया जा सकता है।

Test of partnership

Section 6

Section 6 of the Indian Partnership Act provides the mode of determining the existence of a partnership. The following are the provisions in Section 6:

1. While determining whether an association of persons is a firm or if a person is a partner to a firm, the real relation shown by relevant facts between the parties must be examined.
2. Sharing profits from a property held by persons jointly does not automatically qualify such persons as partners.
3. A person can hold a receipt of the share in profits or receipt of payment that is contingent upon the profits, but that does not make him a partner. The following are such persons:
 - Servant or agent who receives remuneration or commission.
 - Widow or child of a deceased partner who receives an annuity.
 - Moneylender to the partnership business.
 - The previous owner or part owner who has consideration for the sale of the goodwill of the business or share of it.
 - साझेदारी की परीक्षा (**Test of Partnership**) – धारा 6:
 - धारा 6 साझेदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने की विधि बताती है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं—
 - यह निर्धारित करते समय कि व्यक्तियों का कोई समूह (association of persons) फर्म है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति साझेदार है या नहीं, पक्षों के बीच वास्तविक संबंध (real relation) को संबंधित तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए।
 - संयुक्त रूप से रखी गई संपत्ति (joint property) से होने वाले लाभ का बंटवारा अपने-आप में साझेदारी स्थापित नहीं करता।
 - यदि कोई व्यक्ति लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है या लाभ पर आधारित भुगतान (contingent upon profits) प्राप्त करता है, तो मात्र इसी आधार पर उसे साझेदार नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण—
 - • सेवक (servant) या अभिकर्ता (agent), जो पारिश्रमिक (remuneration) या कमीशन (commission) प्राप्त करता है।
 - मृत साझेदार की विधवा (widow) या संतान (child), जिसे वार्षिकी (annuity) प्राप्त होती है।
 - साझेदारी व्यवसाय को ऋण देने वाला धनदाता (moneylender)।
 - पूर्व स्वामी (previous owner) या आंशिक स्वामी (part owner), जिसे व्यवसाय की गुडविल (goodwill) के विक्रय के बदले प्रतिफल (consideration) प्राप्त होता है।

Real criteria for determining partnership

It is clear from Section 6 that the sharing of profits is not the ultimate test for determining whether a partnership exists. The existence of a partnership depends on the actual intention of the parties and the contract drawn up by them. In some cases, an alleged partner might have a share in the profits of the business, but that does not by default make him a partner.

The earlier position was that the share of profits is the criteria for determining partnership, as held in the case of *Waugh v. Carver (1973)*. The House of Lords

overruled this decision in the case of *Cox v. Hickman (1860)*. In this case, Lord Crownworth held that the real test of partnership is mutual agency among the members of the particular association. However, the factor of share of profits cannot be eliminated. Share of profits is certainly an important piece of evidence that helps to determine the existence of a partnership, but not the ultimate test.

साझेदारी निर्धारण का वास्तविक मानदंड (Real Criteria for Determining Partnership):

धारा 6 से यह स्पष्ट होता है कि केवल लाभ का बंटवारा (sharing of profits) ही साझेदारी के अस्तित्व का अंतिम (ultimate) परीक्षण नहीं है। साझेदारी का अस्तित्व पक्षों की वास्तविक मंशा (intention) और उनके द्वारा किए गए अनुबंध (contract) पर निर्भर करता है।

कुछ मामलों में, कोई व्यक्ति व्यवसाय के लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है, लेकिन इससे वह स्वतः साझेदार (partner) नहीं बन जाता। पूर्व में यह माना जाता था कि लाभ का हिस्सा ही साझेदारी निर्धारण का मुख्य आधार है, जैसा कि *Waugh v. Carver* में कहा गया था। किन्तु इस सिद्धांत को *Cox v. Hickman* में अस्वीकार (overrule) कर दिया गया।

इस मामले में लॉर्ड क्रैनवर्थ (Lord Cranworth) ने कहा कि साझेदारी का वास्तविक परीक्षण (real test) साझेदारों के बीच पारस्परिक अभिकरण (mutual agency) है।

हालाँकि, लाभ का बंटवारा पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। यह साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य (important evidence) अवश्य है, लेकिन यह अंतिम परीक्षण (ultimate test) नहीं है।

Kinds of partnership

The various types of partnership are based on two different criteria.

With regard to the duration of the term of partnership:

साझेदारी के प्रकार (Kinds of Partnership):

साझेदारी के विभिन्न प्रकार दो अलग-अलग आधारों (criteria) पर निर्धारित किए जाते हैं।

साझेदारी की अवधि (Duration) के आधार पर:

Partnership at will

when no fixed period is prescribed for the expiration of partnership then it is a partnership at will. According to **Section 7** two conditions need to be fulfilled:

- No agreement about the determination of the fixed period of partnership
- No clause with respect to the determination of partnership.

- **इच्छानुसार साझेदारी (Partnership at Will):**
जब साझेदारी की समाप्ति (expiration) के लिए कोई निश्चित अवधि (fixed period) निर्धारित नहीं की जाती, तब उसे इच्छानुसार साझेदारी (partnership at will) कहा जाता है।
- धारा 7 के अनुसार, इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं—
 - साझेदारी की अवधि (duration) के निर्धारण के संबंध में कोई समझौता न हो।
 - साझेदारी के समाप्त होने (determination) के संबंध में कोई प्रावधान (clause) न हो।

Partnership for a fixed period

When the partners fixed the duration of the partnership firm then after the expiration of the fixed period the partnership comes to an end. When the partners decided to continue with the partnership even after the expiry of the fixed period then it becomes a partnership at will.

On the basis of the extent of the business carried by a partnership

निश्चित अवधि की साझेदारी (Partnership for a Fixed Period):

जब साझेदार साझेदारी फर्म की अवधि (duration) पहले से निर्धारित कर देते हैं, तो उस निश्चित अवधि के समाप्त होने पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है।

यदि साझेदार उस निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद भी साझेदारी को जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो वह इच्छानुसार साझेदारी (partnership at will) बन जाती है।

व्यवसाय के विस्तार (extent of business) के आधार पर:

Particular Partnership (Section 8)

When the partnership is created for completing any project or undertaking. When such an undertaking or project have been completed then partnership comes to an end. The partners have a choice to continue with the firm.

विशिष्ट साझेदारी (Particular Partnership) – धारा 8:

जब साझेदारी किसी विशेष कार्य (project) या उपक्रम (undertaking) को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहा जाता है।

जब वह कार्य या परियोजना पूर्ण हो जाती है, तब साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है।

हालाँकि, साझेदारों के पास यह विकल्प (option) होता है कि वे साझेदारी को आगे भी जारी रखें।

General Partnership

when the partnership is created for the purpose of carrying out the business. There is no particular task that has to be completed. The task is general in nature.

सामान्य साझेदारी (General Partnership):

जब साझेदारी का गठन सामान्य रूप से व्यवसाय (business) करने के उद्देश्य से किया जाता है और कोई विशेष कार्य (specific task) निर्धारित नहीं होता, तब उसे सामान्य साझेदारी कहा जाता है।

इस प्रकार की साझेदारी में कार्य का स्वरूप सामान्य (general) होता है और यह किसी एक निश्चित परियोजना तक सीमित नहीं होती।

Scope of Partnership Act (Section 5)

The partnership arises from the contract but not from the status. The intention of partners is a question of the partnership. the partners may exercise any of its power at time but must not exercise in the pursuance of illegal, fraudulent or misconduct.

If any of the partners have made the contract without the consent of all other partners then the question as to the validity of such contract arises. If all the partners have accepted or ratified the contract then no question as to the validity of such contract arise.

With the consent of all the partners, the partnership can become a member of another firm.

साझेदारी अधिनियम का क्षेत्र (Scope of Partnership Act) – धारा 5:

साझेदारी का जन्म स्थिति (status) से नहीं, बल्कि अनुबंध (contract) से होता है। साझेदारी का निर्धारण साझेदारों की मंशा (intention) पर निर्भर करता है।

साझेदार अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु उन्हें किसी अवैध (illegal), कपटपूर्ण (fraudulent) या दुर्गुण (misconduct) के उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

यदि किसी साझेदार ने अन्य साझेदारों की सहमति के बिना कोई अनुबंध किया है, तो उस अनुबंध की वैधता (validity) का प्रश्न उठता है।

यदि सभी साझेदार उस अनुबंध को स्वीकार (accept) या अनुमोदित (ratify) कर देते हैं, तो उसकी वैधता पर कोई प्रश्न नहीं रहता।

सभी साझेदारों की सहमति से, एक साझेदारी फर्म किसी अन्य फर्म की सदस्य (member) भी बन सकती है।

Partners

The member of a partnership is called partners. it is not mandatory that all the partners are the same or all the partners participate in the conduct of the business or share the profit or

losses equally. The partners are classified depending on the nature of work, the extent of liability, etc. There are basically six types of partner:

- **Active/managing partner:** The partner who takes participation in the conduct of the business daily. This partner is also called an ostensible partner.
- **Sleeping/Dormant:** He does not participate in the conduct of the business but he is bound by the conduct of all the partners.
- **Nominal partner:** He is a partner to the firm only by his name. In reality, he has no significant or real interest in the firm.
- **Partner in profit only:** The partner who agrees to share the profit but does not suffer losses. He is not liable for any liabilities in case of dealing with the third party.
- **Minor partner:** A minor cannot be a partner according to the Indian Contract Act, but he can be admitted to get the benefit of all the partners gives the consent. His will share the profit equally but his liability will be limited in case of loss of the firm.
- **Partner by estoppel:** it means when the person is not a partner but he has represented himself by conduct, or words to another person to be the partner then he cannot deny afterwards. Even though he is not a partner but he becomes the partner by holding out or by estoppel.
- **साझेदार (Partners):**

साझेदारी (partnership) के सदस्यों को साझेदार (partners) कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार समान हों, या सभी व्यवसाय के संचालन में भाग लें, अथवा लाभ-हानि को समान रूप से बाँटें।
- साझेदारों का वर्गीकरण उनके कार्य के स्वरूप, दायित्व (liability) आदि के आधार पर किया जाता है। मुख्यतः साझेदारों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं—
- **सक्रिय/प्रबंध साझेदार (Active/Managing Partner):**

वह साझेदार जो प्रतिदिन व्यवसाय के संचालन में भाग लेता है। इसे प्रकट साझेदार (ostensible partner) भी कहा जाता है।
- **निष्क्रिय/सोया हुआ साझेदार (Sleeping/Dormant Partner):**

यह व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेता, फिर भी अन्य साझेदारों के कार्यों से बंधा होता है।
- **नाममात्र का साझेदार (Nominal Partner):**

यह केवल नाम के लिए साझेदार होता है। वास्तव में इसका फर्म में कोई वास्तविक या महत्वपूर्ण हित नहीं होता।

- **केवल लाभ में साझेदार (Partner in Profit Only):**
यह साझेदार केवल लाभ में हिस्सा लेने के लिए सहमत होता है, लेकिन हानि में भाग नहीं लेता। सामान्यतः यह तीसरे पक्ष के प्रति देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता।
- **नाबालिग साझेदार (Minor Partner):**
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार, नाबालिग साझेदार नहीं बन सकता, किन्तु सभी साझेदारों की सहमति से उसे साझेदारी के लाभ के लिए शामिल किया जा सकता है। वह लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है, परन्तु हानि की स्थिति में उसकी देयता सीमित (limited liability) होती है।
- **प्रतिबंध (Estoppel) द्वारा साझेदार (Partner by Estoppel):**
जब कोई व्यक्ति साझेदार न होते हुए भी अपने आचरण (conduct) या शब्दों (words) द्वारा स्वयं को साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है, तो बाद में वह इससे इंकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, वह “holding out” या “estoppel” के सिद्धांत के आधार पर साझेदार माना जाता है।

Relation of partner with one another

All the partners have a right to create their own terms and condition with regard to the affairs of the business in the partnership deed. The Indian Partnership Act has prescribed the provision to govern the relation of partners and this provision is applicable in case when there is no deed. The **various rights** of the partners are explained below:

- **Right to determine the relationship by contract (Section 11)**

The partnership deed determines the general administration of the partnership like what will be the profit-sharing ratio, who will do what work etc. The partnership contains the rights and duties of the partners.

Such a deed can be made either expressly or by necessary implication. For example, if one partner looks into sales daily and other partners do not object to it, his conduct will be presumed as the right of all the partners in the absence of written agreement. So it can be concluded that all partners create a right for their own.

साझेदारों के बीच संबंध (Relation of Partners with One Another):

सभी साझेदार साझेदारी विलेख (partnership deed) के माध्यम से व्यवसाय के मामलों के संबंध में अपने नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 साझेदारों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान देता है, और ये प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब कोई विलेख (deed) मौजूद नहीं होता।

साझेदारों के विभिन्न अधिकार निम्नलिखित हैं—

- अनुबंध द्वारा संबंध निर्धारित करने का अधिकार

(Right to determine the relationship by contract) – धारा 11:

साझेदारी विलेख, साझेदारी के सामान्य प्रशासन (administration) को निर्धारित करता है, जैसे—लाभ बाँटने का अनुपात (profit-sharing ratio), कौन कौन-सा कार्य करेगा आदि इसमें साझेदारों के अधिकार (rights) और कर्तव्य (duties) भी शामिल होते हैं।

यह विलेख स्पष्ट (express) रूप से या आवश्यक आशय (implied) द्वारा बनाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि एक साझेदार प्रतिदिन बिक्री (sales) का कार्य देखता है और अन्य साझेदार इस पर कोई आपत्ति नहीं करते, तो लिखित समझौते के अभाव में उसका यह कार्य सभी साझेदारों द्वारा स्वीकृत अधिकार माना जाएगा।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साझेदार अपने अधिकार स्वयं भी निर्धारित कर सकते हैं।

Section 27 of the Indian Contract Act, 1872

Agreement in restraint of trade is void

All the agreements which restrain the person from carrying any lawful profession, trade or business are void.

But **Section 11** of the Partnership Act states that the partners can restrain each other from carrying a business other than the firm. but such restraint must contain in the partnership deed.

धारा 27 के अनुसार—

व्यापार पर प्रतिबंध (restraint of trade) लगाने वाले सभी समझौते शून्य (void) होते हैं। अर्थात्, जो भी समझौते किसी व्यक्ति को किसी वैध पेशे, व्यापार या व्यवसाय करने से रोकते हैं, वे अमान्य माने जाते हैं।

किन्तु धारा 11 के अनुसार, साझेदार आपस में यह सहमति कर सकते हैं कि वे फर्म के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेंगे।

हालाँकि, ऐसा प्रतिबंध (restraint) साझेदारी विलेख (partnership deed) में स्पष्ट रूप से शामिल होना चाहिए।

Rights of the Partners

- **Right to take part in the conduct of the firm's business:** **Section 12(a)** provides that every partner has the right to be involved in the conduct of the firm's business. All partners have the right to manage the firm's business.
- **Right to express opinion:** Section 12(c) provides that all partners can freely express their opinion in matters concerning the firm's business. However, before a decision is made based on an opinion of a partner, the consent of other partners must be obtained.
- **Right to have access to books of the firm:** Section 12(d) of the Act provides that every partner has the right to look into the books of the firm, whether the books concern the accounts of the firm or not.

- **Right to profit:** As per [Section 13\(b\)](#), all partners must equally share profits earned through the business.
- **Right to interest on capital:** Section 13(c) provides that on an agreement, the partners of a firm have the right to claim interest on the firm's profits from the capital.
- **Right to interest on advances made by partner:** In some cases the firm may need extra money apart from the capital. In such cases, a partner may make advances to the firm and he may also claim interest on such advances.
- **Right to indemnity:** Section 13(e) of the Act provides that a partner may make some payments and incur liabilities while acting on behalf of the firm. The firm shall indemnify a partner in respect of such payments and liabilities, whether it was made in ordinary course of business or in emergency.
- **Right to dissolve the partnership:** [Section 44](#) provides that a partner has the right to file a suit to dissolve the partnership. The court may dissolve firm on any of the grounds given below:
 1. Unsoundness of mind of a partner, where the suit shall be brought by another partner or the next friend of the unsound partner;
 2. Permanent incapability of another partner to perform his duties;
 3. Another partner is guilty of conduct that prejudices the business of the firm;
 4. Committing breach of agreement by another partner by wilfully or persistently;
 5. Transfer of interest in firm by another partner to a third person;
 6. Business of firm cannot be carried on due to losses;
 7. Any other ground which makes it just and equitable to dissolve the partnership.
- [Section 46](#) provides that after dissolution, a partner has the right to wind up the business of the firm. On dissolution, every partner or his representative is entitled, as against all the other partners, to have the firm's property applied in payment of debts and liabilities of the firm, and then have the surplus distributed among the partners or their representatives.
- **Right to not get expelled:** [Section 33](#) provides that all partners have right to not get expelled except on certain grounds and they must be given reasonable warning and opportunity of explanation before the expulsion.

- **Right to prevent introduction of new person:** Section 31 provides that every partner has the right to prevent the introduction of a new partner without his consent to the firm, unless the agreement has expressly provided that such introduction is permitted.
- **Right to retire:** Section 32 of the Act provides that a person has right to retire with the consent of other partners, unless the requirement of consent is waived by the agreement. The partners can retire by simply providing a notice to other partners in partnerships at will.

साझेदारों के अधिकार (Rights of the Partners):

- फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार — धारा 12(a):

प्रत्येक साझेदार को फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। सभी साझेदारों को प्रबंधन (management) का अधिकार प्राप्त होता है।

- अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार — धारा 12(c):

सभी साझेदार फर्म के व्यवसाय से संबंधित मामलों में स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु किसी निर्णय से पहले अन्य साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है।

- फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार — धारा 12(d):

प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों (books of accounts) का निरीक्षण करने का अधिकार होता है।

- लाभ प्राप्त करने का अधिकार — धारा 13(b):

सभी साझेदार व्यवसाय से प्राप्त लाभ को समान रूप से बाँटने के अधिकारी होते हैं (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो)।

- पूँजी पर ब्याज का अधिकार — धारा 13(c):

समझौते के अनुसार, साझेदार अपनी पूँजी पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।

- अग्रिम राशि (Advances) पर ब्याज का अधिकार:

यदि कोई साझेदार फर्म को अतिरिक्त धन देता है, तो वह उस पर ब्याज का दावा कर सकता है।

- क्षतिपूर्ति (Indemnity) का अधिकार — धारा 13(e):

यदि कोई साझेदार फर्म की ओर से कार्य करते हुए कोई भुगतान करता है या दायित्व उठाता है, तो फर्म उसे उसकी क्षतिपूर्ति (indemnify) करेगी, चाहे वह सामान्य व्यापार में हो या आपात स्थिति में।

- साझेदारी को भंग (Dissolve) करने का अधिकार — धारा 44:

साझेदार न्यायालय में वाद (suit) दायर कर साझेदारी को भंग करा सकता है। न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर फर्म को भंग कर सकता है—

किसी साझेदार का अस्वस्थ मस्तिष्क (unsoundness of mind)

किसी साझेदार की स्थायी अक्षमता (permanent incapability)

किसी साझेदार का ऐसा आचरण जो फर्म के व्यवसाय को हानि पहुँचाए

किसी साझेदार द्वारा समझौते का जानबूझकर या लगातार उल्लंघन

किसी साझेदार द्वारा अपनी हिस्सेदारी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना

लगातार हानि के कारण व्यवसाय का संचालित न हो पाना

कोई अन्य कारण जो न्यायोचित (just and equitable) हो

- फर्म के समापन (Winding up) का अधिकार — धारा 46:

विघटन के बाद प्रत्येक साझेदार या उसका प्रतिनिधि फर्म के कार्यों को समाप्त (wind up) करने का अधिकार रखता है। फर्म की संपत्ति का उपयोग पहले ऋणों और दायित्वों के भुगतान में किया जाता है, और शेष राशि साझेदारों में बाँटी जाती है।

- निष्कासन (Expulsion) से सुरक्षा का अधिकार — धारा 33:

किसी साझेदार को बिना उचित कारण के निष्कासित नहीं किया जा सकता। उसे पहले उचित सूचना (notice) और स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए।

- नए साझेदार के प्रवेश को रोकने का अधिकार — धारा 31:

कोई भी साझेदार अपनी सहमति के बिना किसी नए व्यक्ति को साझेदारी में शामिल होने से रोक सकता है, जब तक कि समझौते में इसके विपरीत प्रावधान न हो।

- सेवानिवृत्ति (Retirement) का अधिकार — धारा 32:

कोई साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से साझेदारी से अलग हो सकता है, जब तक कि समझौते में सहमति की आवश्यकता को हटाया न गया हो। इच्छानुसार साझेदारी (partnership at will) में, साझेदार केवल सूचना (notice) देकर भी सेवानिवृत्त हो सकता है।

Relations of partners to third parties

Section 18 to 22 of the Act talks about the relation of partners third parties

Section 18 prescribes that the partners are an agent of the firm for the purpose of conducting the affairs of the business. The partners act as the principal and agent as well. when he performs the act in his own interest he is the principal and when he does in the interest of another partner then he is an agent. He is not an agent for the dealings or the transactions between the partners themselves.

Section 19 states that any act which is performed by the partners in the usual course of its business binds the firm itself. The authority to bind the firm is implied authority

Section 20 states that partners can make a contract to restrict or expand the implied authority of a partner.

Section 21 states that if any act is done by any partners in case of an emergency which a prudent man would do, then such acts need to bind the firm.

Section 22 specifies that if any act is done by any partner then it must be done in the name of the firm or in such manner which binds the firm.

तीसरे पक्ष के साथ साझेदारों का संबंध (Relations of Partners to Third Parties):

धारा 18 से 22 में साझेदारों और तीसरे पक्ष (third parties) के बीच संबंध का वर्णन किया गया है।

- धारा 18:

साझेदार, फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए फर्म के अभिकर्ता (agent) होते हैं। प्रत्येक साझेदार एक साथ प्रधान (principal) और अभिकर्ता (agent) दोनों होता है। जब वह अपने हित में कार्य करता है, तो वह प्रधान होता है, और जब अन्य साझेदारों के हित में कार्य करता है, तो वह अभिकर्ता होता है।

हालाँकि, साझेदार आपस के लेन-देन (mutual dealings) में एक-दूसरे के अभिकर्ता नहीं होते।

- धारा 19:

साझेदार द्वारा व्यवसाय के सामान्य (usual) क्रम में किया गया कोई भी कार्य फर्म को बाध्य (bind) करता है। फर्म को बाध्य करने की यह शक्ति “निहित प्राधिकरण” (implied authority) कहलाती है।

- धारा 20:

साझेदार आपस में अनुबंध (contract) करके किसी साझेदार की निहित प्राधिकरण (implied authority) को सीमित (restrict) या विस्तारित (expand) कर सकते हैं।

- धारा 21:

आपातकाल (emergency) की स्थिति में, यदि कोई साझेदार ऐसा कार्य करता है जो एक समझदार व्यक्ति (prudent man) करता, तो वह कार्य फर्म को बाध्य करेगा।

- धारा 22:

यदि कोई साझेदार कोई कार्य करता है, तो उसे फर्म के नाम से या ऐसे तरीके से करना चाहिए जिससे फर्म बाध्य (bind) हो सके।

Duties of partners

- **Duty of greatest common advantage:** As per [Section 9](#) of the Act, it is incumbent upon the partners to carry on their business for the greatest common advantage of the firm. The partners must act so that all the partners benefit and secure the maximum profits. No partner should act for their personal gain.
- **Duty of good faith:** As per Section 9, the partners must act just to each other. The relationship of partnership is on mutual trust and hence, there must be good faith between them. A partnership is of fiduciary nature and thus, at every stage of a partnership, the partners must act just and faithful to one another.
- **Duty to render true accounts:** Partners of a firm have a duty to render true accounts as per Section 9. A partner of a firm must keep and render true and complete accounts of the partnership firm's business. He must make it available to other partners or their representatives when required.
- **Duty to render full information:** As per Section 9, partners of a firm have a duty to provide true and full information regarding the business. Partners are agents of each other and hence, partners must communicate all information regarding the running of the business in a complete and truthful manner to each other.
- **Duty to not carry another business:** As per [Section 11\(2\)](#) of the Act, a partner must not conduct a business other than that of the firm. Partners can restrain one another from carrying on another business, provided that such restraint is reasonable.
- **Duty to act diligently:** As per [Section 12\(b\)](#), a firm's partner must act diligently in the business.
- **Duty to perform without remuneration:** As per [Section 13\(a\)](#), every partner must perform and attend to the firm's business without

expecting remuneration. There is a presumption that all partners are to work for the common advantage of the firm.

- **Duty to share losses:** As per Section 13(b) of the Act, partners must share losses in the proportions as provided by the partnership agreement. If the agreement does not provide it, it must be shared in the proportion that they share the profits.
- **Duty to indemnify for wilful neglect:** As per Section 13(f), a partner shall indemnify his firm for any of the losses caused to it due to his wilful neglect during the course of the business. Wilful neglect refers to an act that is deliberate and intentional.
- **Duty to not assign his rights:** No partner can assign his rights in a partnership firm to a third person in order to make him a partner.
- **Duty to act within authority:** Every person has to act within the authority that he has conferred upon him as per the partnership agreement.
- **Duty to account private profits:** Section 16(a) provides that no partner can use the partnership firm's property for private use, or use any profits derived from the partnership business for his own advantage. If the property of profits of a firm is ever used for personal advantage, it must be accounted for.
- **Duty not to compete:** [Section 16\(b\)](#) states that no partner of a firm can carry on another business simultaneously, except with the consent of other partners. On the failure of obtaining the consent, he must account for all the profits he made as a result of that and must compensate for the losses sustained by the firm if any.
- **Duty to properly use the firm's property:** [Sections 14](#) and [15](#) of the Act provide that the property of the firm must be used solely for the purpose of the firm's business and not for private purposes. The term 'property of the firm' covers all properties and rights and interests in a property originally acquired by the firm for the purpose of running the business. The goodwill of the business is also a property of the firm.
- **साझेदारों के कर्तव्य (Duties of Partners):**
- **सर्वाधिक सामान्य लाभ का कर्तव्य – धारा 9:**
साझेदारों का कर्तव्य है कि वे फर्म के अधिकतम सामूहिक लाभ (greatest common advantage) के लिए कार्य करें। कोई भी साझेदार केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा।
- **सद्भाव (Good Faith) का कर्तव्य – धारा 9:**
साझेदारों को आपस में न्यायपूर्ण और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। साझेदारी का

संबंध पारस्परिक विश्वास (mutual trust) पर आधारित होता है, इसलिए इसमें पूर्ण सद्भाव आवश्यक है।

- **सही लेखा प्रस्तुत करने का कर्तव्य – धारा 9:**
साझेदारों को फर्म के व्यवसाय के सही और पूर्ण लेखे (accounts) रखने और प्रस्तुत करने का कर्तव्य होता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य साझेदारों को उपलब्ध कराना होता है।
- **पूर्ण जानकारी देने का कर्तव्य – धारा 9:**
साझेदारों को व्यवसाय से संबंधित सभी आवश्यक और सही जानकारी एक-दूसरे को देनी चाहिए।
- **अन्य व्यवसाय न करने का कर्तव्य – धारा 11(2):**
कोई भी साझेदार फर्म के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं करेगा, जब तक कि अन्य साझेदारों की सहमति न हो।
- **परिश्रमपूर्वक कार्य करने का कर्तव्य – धारा 12(b):**
प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय में लगन और परिश्रम (diligently) से कार्य करना चाहिए।
- **बिना पारिश्रमिक कार्य करने का कर्तव्य – धारा 13(a):**
प्रत्येक साझेदार को फर्म के कार्य बिना किसी वेतन (remuneration) की अपेक्षा के करना चाहिए (जब तक कि अन्यथा समझौता न हो)।
- **हानि को साझा करने का कर्तव्य – धारा 13(b):**
साझेदारों को हानि को समझौते के अनुसार बाँटना होगा; यदि कोई प्रावधान नहीं है, तो लाभ के अनुपात में हानि बाँटी जाएगी।
- **जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति – धारा 13(f):**
यदि किसी साझेदार की जानबूझकर की गई लापरवाही (wilful neglect) से फर्म को हानि होती है, तो वह उसकी भरपाई (indemnify) करेगा।
- **अधिकारों का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य:**
कोई साझेदार अपने अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करके उसे साझेदार नहीं बना सकता।
- **प्राधिकरण के भीतर कार्य करने का कर्तव्य:**
प्रत्येक साझेदार को अपने अधिकार (authority) की सीमा के भीतर ही कार्य करना चाहिए।
- **निजी लाभ का लेखा देने का कर्तव्य – धारा 16(a):**
कोई साझेदार फर्म की संपत्ति या व्यवसाय से प्राप्त लाभ का निजी उपयोग नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है, तो उसे उसका हिसाब देना होगा।

- **प्रतिस्पर्धा न करने का कर्तव्य – धारा 16(b):**
कोई साझेदार, अन्य साझेदारों की सहमति के बिना समान व्यवसाय नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे अपने द्वारा अर्जित लाभ का हिसाब देना होगा और फर्म को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।
- **फर्म की संपत्ति का उचित उपयोग – धारा 14 व 15:**
फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल फर्म के व्यवसाय के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए।
“फर्म की संपत्ति” में वे सभी संपत्तियाँ, अधिकार और हित शामिल होते हैं, जो व्यवसाय के संचालन के लिए प्राप्त किए गए हैं। व्यवसाय की गुडविल (goodwill) भी फर्म की संपत्ति मानी जाती है।

When do Rights and Duties change?

The existing relationship between the partners come to an end when there is a change in the constitution of the firms. Such changes in the constitution of the firm may occur due to the following reasons [\(Section 17\)](#)

- Expiration of term of the firm.
- Carrying out the additional business other than agreed upon.
- Changes in the composition of members due to admission, retirement or the death of a partner.

The duties and rights of partners remain the same until there is any change in agreement but such right and duties may vary or modified by creating a fresh agreement.

अधिकार और कर्तव्य कब बदलते हैं?

(When do Rights and Duties change?) – धारा 17:

साझेदारों के बीच विद्यमान संबंध तब समाप्त या परिवर्तित हो जाते हैं, जब फर्म की संरचना (constitution of firm) में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं—

- फर्म की निर्धारित अवधि (term) का समाप्त होना।
- सहमति से निर्धारित व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय करना।
- साझेदारों की संरचना (composition) में परिवर्तन, जैसे—नए साझेदार का प्रवेश (admission), सेवानिवृत्ति (retirement) या किसी साझेदार की मृत्यु (death)।

साझेदारों के अधिकार (rights) और कर्तव्य (duties) तब तक समान रहते हैं, जब तक कि समझौते (agreement) में कोई परिवर्तन न किया जाए।

हालाँकि, नए समझौते (fresh agreement) के माध्यम से इन अधिकारों और कर्तव्यों में परिवर्तन (modification) किया जा सकता है।

Status of a minor

Section 30 states the legal provision related to the minor according to **Section 18** of the Indian Contract act 1872, no person below the age of 18 years can enter into the contract which implies that no minor can enter into a contract. But **Section 30** states that the minor cannot be a partner in a partnership firm but he can be admitted to benefit from the partnership firm. The minor will be liable to get only the benefits from the partnership but is not liable for any losses or liability. The minor can be admitted to the partnership only with the consent of all the partners.

There are various rights that are granted to the minor.

नाबालिग की स्थिति (Status of a Minor):

धारा 30 में नाबालिग (minor) से संबंधित विधिक प्रावधान दिए गए हैं।

धारा 11 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति वैध अनुबंध (contract) नहीं कर सकता, अर्थात् नाबालिग अनुबंध करने में अयोग्य होता है।

किन्तु धारा 30 के अनुसार, नाबालिग साझेदारी फर्म का साझेदार (partner) नहीं बन सकता, परन्तु उसे सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी के लाभ (benefits) के लिए शामिल किया जा सकता है।

नाबालिग केवल लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, लेकिन वह फर्म के किसी भी नुकसान (loss) या दायित्व (liability) के लिए उत्तरदायी नहीं होता।

नाबालिग को साझेदारी में शामिल करने के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है।

नाबालिग को कुछ विशेष अधिकार (rights) भी प्रदान किए जाते हैं।

Various rights are as follows:

- Right to inspect the books of account
- Rights to share the profits from the firm
- Rights to sue any partner or all for his share of benefit or profit
- He has a limited liability which means his personal assets may not be disposed of to pay the firm debts
- A minor has a right to become a partner on attaining the age of 18 years.
- **नाबालिग के अधिकार (Rights of a Minor):**
 - फर्म की लेखा-पुस्तकों (books of account) का निरीक्षण करने का अधिकार।
 - फर्म के लाभ (profits) में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार।
 - अपने लाभ या हिस्से के लिए किसी एक या सभी साझेदारों के विरुद्ध वाद (suit) दायर करने का अधिकार।
 - उसकी देयता सीमित (limited liability) होती है, अर्थात् फर्म के ऋणों के भुगतान के

लिए उसकी निजी संपत्ति (personal assets) का उपयोग नहीं किया जा सकता।

- 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर साझेदार (partner) बनने का अधिकार।

Liabilities of a minor

- A minor has Limited liability. If minor is declared as insolvent his share will be kept in the possession of official liquidator.
- If after attaining the age of 18 years he decided to become the partner then he has to give public notice within 6 months of attaining the majority. If notice not given then minor will become liable for all the acts of others until the notice is given
- When a minor partner becomes the major he will be liable for the acts of all partners to the third parties.
- If he decided to become a full-time partner then he will be considered as a normal partner and will take part in the conduct of the business.
- **नाबालिग की देयताएँ (Liabilities of a Minor):**
- • नाबालिग की देयता सीमित (limited liability) होती है। यदि नाबालिग को दिवालिया (insolvent) घोषित किया जाता है, तो उसका हिस्सा आधिकारिक परिसमापक (official liquidator) के नियंत्रण में रखा जाता है।
- • 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद यदि वह साझेदार बनना चाहता है, तो उसे 6 माह के भीतर सार्वजनिक सूचना (public notice) देनी होती है। यदि वह सूचना नहीं देता, तो वह अन्य साझेदारों के कार्यों के लिए उत्तरदायी (liable) हो जाएगा, जब तक कि सूचना नहीं दी जाती।
- • जब नाबालिग साझेदार वयस्क (major) बन जाता है, तो वह तीसरे पक्ष (third parties) के प्रति सभी साझेदारों के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है।
- • यदि वह पूर्णकालिक (full-time) साझेदार बनने का निर्णय लेता है, तो उसे सामान्य साझेदार (normal partner) के रूप में माना जाएगा और वह व्यवसाय के संचालन में भाग लेगा।

Liabilities

- **Liability of partners for the acts of the firm (Section 25):** All the partners is jointly and severally liable for the acts of the firms. He is liable only for those acts which are done at the time he is a partner.

- **Liability of a firm for the wrongful act of partner (Section 26):** When any wrongful act or omission is done by any of its partners in the ordinary course of its business or with the consent of others partners then the firm is liable to the same extent as a partner.
- **Liability of a firm for the misapplications by partner (Section 27):** when any partner acting as an agent receives the money from the third party and misapplies it or the firm receives the money and money are misappropriated by any of its partners then the firm is liable to pay for the loss suffered.
- **देयताएँ (Liabilities):**
- **फर्म के कार्यों के लिए साझेदारों की देयता – धारा 25:**
सभी साझेदार फर्म के कार्यों के लिए संयुक्त (joint) और पृथक (several) रूप से उत्तरदायी होते हैं। वे केवल उन्हीं कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो उनके साझेदार रहने के दौरान किए गए हों।
- **साझेदार के गलत कार्यों के लिए फर्म की देयता – धारा 26:**
यदि कोई साझेदार व्यवसाय के सामान्य क्रम (ordinary course of business) में या अन्य साझेदारों की सहमति से कोई गलत कार्य (wrongful act) या चूक (omission) करता है, तो फर्म उसी सीमा तक उत्तरदायी होती है, जितना वह साझेदार होता है।
- **साझेदार द्वारा धन के दुरुपयोग के लिए फर्म की देयता – धारा 27:**
यदि कोई साझेदार अभिकर्ता (agent) के रूप में कार्य करते हुए तीसरे पक्ष से धन प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोग (misapplication) करता है, या फर्म को प्राप्त धन का कोई साझेदार गबन (misappropriation) करता है, तो फर्म उस हानि (loss) के लिए उत्तरदायी होती है।

How is registration done?

[Section 58](#) explains the procedure of the registration of a partnership firm.

- **Making an application to Registrar:** Any of its partners can send an application along with the prescribed fee and copy of partnership deed to the registrar of the area in which any place of business is proposed to be situated or is situated. Such a statement shall be signed by all of its partners. Such a statement should contain:
 - Name of the firm
 - Principal place of business
 - Any other place where the business is carried on
 - Duration of partnership firm

- Name and address of all partners of a firm
- The date on which each partner joined the firm
- **Verification:** Each partner who has signed the statements needs to be verified.
- The **name of the firm** shall not contain any name resembling the name of Crown, Emperor, king, Royal, Emperors', or any other words implying or expressing the sanction of the government.

Section 59 states that when the Registrar is satisfied that the conditions of **Section 58** are complied with then he shall record an entry of the statement in a register called the Register of Firms, and shall file the statement.

देयताएँ (Liabilities):

- फर्म के कार्यों के लिए साझेदारों की देयता – धारा 25:

सभी साझेदार फर्म के कार्यों के लिए संयुक्त (joint) और पृथक (several) रूप से उत्तरदायी होते हैं। वे केवल उन्हीं कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो उनके साझेदार रहने के दौरान किए गए हों।

- साझेदार के गलत कार्यों के लिए फर्म की देयता – धारा 26:

यदि कोई साझेदार व्यवसाय के सामान्य क्रम (ordinary course of business) में या अन्य साझेदारों की सहमति से कोई गलत कार्य (wrongful act) या चूक (omission) करता है, तो फर्म उसी सीमा तक उत्तरदायी होती है, जितना वह साझेदार होता है।

- साझेदार द्वारा धन के दुरुपयोग के लिए फर्म की देयता – धारा 27:

यदि कोई साझेदार अभिकर्ता (agent) के रूप में कार्य करते हुए तीसरे पक्ष से धन प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोग

(misapplication) करता है, या फर्म को प्राप्त धन का कोई साझेदार गबन (misappropriation) करता है, तो फर्म उस हानि (loss) के लिए उत्तरदायी होती है।

Non-registration of partnership firm

In India, it is not compulsory to register the partnership and no penalty is being imposed for non-registration but if we talk about English law it is compulsory to register partnership firm and if it is not registered then the penalty is imposed. Non-registration leads to a certain disability in accordance with Section 69 of the Act.

Effect of non-registration ([Section 69](#))

- No suit can be initiated in civil court by the firm or other co-partners against the third party
- In case of breach of contract by the third party; the suit cannot be brought in any civil suit. The suit must be filed by the one whose name is registered as a partner in a register of the firm.
- No partners can claim a relief of set-off.

- Any action which is brought out by the third party against the firm having a value of Rs 100 cannot be set off by the firm or any of its partners.
- An aggrieved person cannot sue against firms or other partners

Generally, no action can be brought against the firm or the partners but there is an *exception to it*. *In a case when the firm is dissolved it can bring a suit for the realization of his share in the firm's property.*

Non-registrations do not affect the following rights

- A third party can bring a suit against the firm
- Right of the partners or firm to claim a relief of set off the claim for the value which does not exceed Rs 100
- Power of official liquidator, official assignees to release the property of insolvent partners and brings a legal action
- Partner right to claim for the realization of his share in case of dissolution of the firm

साझेदारी फर्म का अपंजीकरण (Non-registration of Partnership Firm):
भारत में साझेदारी का पंजीकरण (registration) अनिवार्य नहीं है और अपंजीकरण के लिए कोई दंड (penalty) भी निर्धारित नहीं है। जबकि अंग्रेजी विधि (English law) में साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है और इसके अभाव में दंड लगाया जाता है। हालाँकि, अपंजीकरण के कारण कुछ विधिक अयोग्यताएँ (disabilities) उत्पन्न होती हैं, जैसा कि धारा 69 में वर्णित है।

अपंजीकरण के प्रभाव (Effect of Non-registration) – धारा 69:

- फर्म या साझेदार तीसरे पक्ष (third party) के विरुद्ध सिविल न्यायालय (civil court) में वाद (suit) दायर नहीं कर सकते।
- यदि तीसरे पक्ष द्वारा अनुबंध (contract) का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। वाद केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसका नाम फर्म के पंजीकरण रजिस्टर में साझेदार के रूप में दर्ज हो।
- कोई भी साझेदार “सेट-ऑफ” (set-off) का दावा नहीं कर सकता।

- यदि तीसरे पक्ष द्वारा फर्म के विरुद्ध ₹100 से अधिक का दावा किया जाता है, तो फर्म या उसके साझेदार उस दावे के विरुद्ध सेट-ऑफ का उपयोग नहीं कर सकते।

- कोई भी पीड़ित व्यक्ति (aggrieved person) फर्म या अन्य साझेदारों के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता (कुछ सीमाओं के साथ)।

सामान्यतः, अपंजीकृत फर्म या उसके साझेदारों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही सीमित हो जाती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद (exceptions) भी हैं।

यदि फर्म का विघटन (dissolution) हो जाता है, तो साझेदार अपनी हिस्सेदारी (share) की प्राप्ति के लिए वाद दायर कर सकता है।

अपंजीकरण से प्रभावित न होने वाले अधिकार (Rights not affected by Non-registration):

- तीसरा पक्ष (third party) फर्म के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है।

- साझेदार या फर्म ₹100 तक के दावे के लिए सेट-ऑफ का अधिकार रख सकते हैं।

- आधिकारिक परिसमापक (official liquidator) या आधिकारिक असाइनी (official assignee) को दिवालिया साझेदार की संपत्ति को मुक्त (realize) करने और कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होता है।

- फर्म के विघटन की स्थिति में साझेदार अपनी हिस्सेदारी की प्राप्ति के लिए दावा कर सकता है।

Introduction or Admission of partner [\(Section 31\)](#)

As per Section 31, no person can be introduced as a new partner to the firm without the consent of other partners. This is, however, subject to the provisions in the agreement of partnership and Section 30, which deals with minor partners.

Modes of introduction

The following are the modes of introduction of a partner:

1. With the consent of all partners
2. Introduction as per the contract between partners
3. A minor admitted to the benefit of the partnership becoming a partner

साझेदार का प्रवेश / अभिग्रहण (**Introduction or Admission of Partner**) – धारा 31:

धारा 31 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को सभी साझेदारों की सहमति के बिना फर्म में नए साझेदार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।

हालाँकि, यह साझेदारी समझौते (partnership agreement) के प्रावधानों तथा धारा 30 (जो नाबालिग साझेदार से संबंधित है) के अधीन होता है।

साझेदार के प्रवेश के तरीके (**Modes of Introduction**):

नए साझेदार को निम्नलिखित तरीकों से शामिल किया जा सकता है—

1. सभी साझेदारों की सहमति से।
2. साझेदारों के बीच हुए अनुबंध (contract) के अनुसार।
3. जब नाबालिग, जिसे पहले साझेदारी के लाभ के लिए शामिल किया गया था, वयस्क (major) होने पर साझेदार बन जाता है।

Rights of incoming partner

1. Right to manage partnership business
2. Right to access books of firm
3. Right to capital, profit and loss
4. Right to dissolve partnership
5. Right to indemnification of losses

नए साझेदार के अधिकार (**Rights of Incoming Partner**):

1. साझेदारी के व्यवसाय के प्रबंधन (management) में भाग लेने का अधिकार।
2. फर्म की लेखा-पुस्तकों (books of account) का निरीक्षण करने का अधिकार।

3. पूँजी (capital), लाभ (profit) और हानि (loss) में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार।
4. साझेदारी को भंग (dissolve) करने का अधिकार।
5. हानि के लिए क्षतिपूर्ति (indemnification) प्राप्त करने का अधिकार।

Liabilities of incoming partner

A partner's liabilities are only with respect to transactions subsequent to becoming a partner. The same is provided under [Section 30\(2\)](#). However, the incoming partner and co-partners can enter into an agreement where it provides that the incoming partner can be held liable for obligations of the firm prior to his arrival.

नए साझेदार की देयताएँ (Liabilities of Incoming Partner):

नए साझेदार की देयता सामान्यतः केवल उन लेन-देन (transactions) तक सीमित होती है, जो उसके साझेदार बनने के बाद किए गए हों। यह सिद्धांत धारा 31(2) में निहित है।

हालाँकि, नया साझेदार और अन्य साझेदार आपस में ऐसा समझौता (agreement) कर सकते हैं, जिसके अनुसार नया साझेदार फर्म की पूर्व देनदारियों (prior obligations) के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है।

Retirement of partner ([Section 32](#))

Section 32 of Act talks about the retirement of partners. When the partner withdraws from the partnership by dissolving it then it is dissolution but not a retirement.

Any partner may retire:

- When there is a partnership at will, by serving a notice to all the existing partners
- When there is an express agreement among the partners
- When the consent of all the partners is given
- **साझेदार का सेवानिवृत्ति (Retirement of Partner) – धारा 32:**
- धारा 32 साझेदार के सेवानिवृत्ति (retirement) से संबंधित प्रावधान करती है। जब कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति कहा जाता है; जबकि यदि साझेदारी ही समाप्त हो जाए, तो उसे विघटन (dissolution) कहा जाता है, न कि सेवानिवृत्ति।
- कोई भी साझेदार निम्नलिखित परिस्थितियों में सेवानिवृत्त हो सकता है—

- **इच्छानुसार साझेदारी (Partnership at will)** के मामले में, सभी साझेदारों को नोटिस (notice) देकर।
- जब साझेदारों के बीच कोई स्पष्ट समझौता (express agreement) हो।
- जब सभी साझेदार अपनी सहमति (consent) प्रदान करें।

Liabilities of retired partner

A retired partner continues to be liable for the acts of firms and other partners till he or any other partners give public notice about his retirement. When the third party does not know that he was a partner and deals with the firm; then in such case a retired partner is not liable. If it is a partnership at will then there is no requirement to give public notice about his retirement.

The outgoing partner may enter into an agreement to not carry similar business or activities within a specified period of time.

सेवानिवृत्त साझेदार की देयताएँ (Liabilities of Retired Partner):

सेवानिवृत्त साझेदार (retired partner) फर्म और अन्य साझेदारों के कार्यों के लिए तब तक उत्तरदायी बना रहता है, जब तक कि उसके

सेवानिवृत्ति (retirement) की सार्वजनिक सूचना (public notice) नहीं दे दी जाती।

यदि कोई तीसरा पक्ष (third party) यह नहीं जानता कि वह पहले साझेदार था और वह फर्म के साथ लेन-देन करता है, तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त साझेदार उत्तरदायी नहीं होगा।

इच्छानुसार साझेदारी (partnership at will) के मामले में, सेवानिवृत्ति के लिए सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक नहीं होता।

सेवानिवृत्त साझेदार एक समझौता (agreement) भी कर सकता है कि वह एक निश्चित अवधि (specified period) तक समान व्यवसाय (similar business) या गतिविधि नहीं करेगा।

Expulsion of partner ([Section 33](#))

A partner can be expelled only when below three conditions are satisfied:

- Expulsion of the partner is necessary for the interest of the partnership
- Notice is served to the expelled partner
- An opportunity of being heard is given to the expelled partner

If the above three conditions are not fulfilled then such expulsion will be considered as null and void.

साझेदार का निष्कासन (Expulsion of Partner) – धारा 33:

किसी साझेदार को केवल निम्नलिखित तीन शर्तों के पूरा होने पर ही निष्कासित (expel) किया जा सकता है—

- साझेदारी के हित (interest of the firm) में निष्कासन आवश्यक हो
 - निष्कासित किए जाने वाले साझेदार को पूर्व सूचना (notice) दी गई हो
 - उसे अपनी बात रखने का उचित अवसर (opportunity of being heard) दिया गया हो
- यदि उपरोक्त तीनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो ऐसा निष्कासन शून्य (null and void) माना जाएगा

Insolvency of a partner ([Section 34](#))

When a partner is declared as insolvent by the court, it leads to the following consequences:

- He ceases to be the partner of a partnership firm from the date of adjudication
- His estate which is in possession of official liquidator ceases to be liable for any acts of the firm whether the partnership subsequently dissolves or not
- Partnership ceases to be liable for any act of insolvency partner
- **साझेदार का दिवालियापन (Insolvency of a Partner) – धारा 34:**
- जब किसी साझेदार को न्यायालय (court) द्वारा दिवालिया (insolvent) घोषित किया जाता है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं—
 - वह निर्णय (adjudication) की तिथि से ही साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं रहता।
 - उसकी संपत्ति (estate), जो आधिकारिक परिसमापक (official liquidator) के नियंत्रण में होती है, फर्म के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं रहती, चाहे साझेदारी बाद में भंग (dissolve) हो या नहीं।
 - साझेदारी फर्म भी उस दिवालिया साझेदार के किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं रहती।

Liability of estate of a deceased person ([Section 35](#))

Generally, the partnership comes to end on the death of a partner but if there is a contract between partners to continue with the partnership on the death of a partner then surviving partner continues with the business after clearing the deceased partner estate from any liability for the future acts of the firms.

मृत साझेदार की संपत्ति की देयता (Liability of Estate of a Deceased Partner) – धारा 35:

सामान्यतः, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी समाप्त (dissolve) हो जाती है।

किन्तु, यदि साझेदारों के बीच ऐसा अनुबंध (contract) हो कि किसी साझेदार की मृत्यु के बाद भी साझेदारी जारी रहेगी, तो शेष (surviving) साझेदार व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।

ऐसी स्थिति में, मृत साझेदार की संपत्ति (estate) को फर्म के भविष्य के कार्यों (future acts) के लिए किसी भी देयता (liability) से मुक्त कर दिया जाता है।

Liability of outgoing partner [\(Section 36\)](#)

The outgoing partner is restricted to perform acts like:

- Using the name of the firm
- Representing himself as a partner
- Make the customer of the firm in which he was a partner as its own.

The outgoing partner may enter into an agreement not to carry similar business or activities within a specified period of time. After the specified period, the outgoing partner is allowed to carry on a similar business or advertise it.

निवृत्त (Outgoing) साझेदार की देयता – धारा 36:

निवृत्त (outgoing) साझेदार को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है—

- फर्म के नाम (name of the firm) का उपयोग करना।
- स्वयं को साझेदार (partner) के रूप में प्रस्तुत करना।
- जिस फर्म में वह साझेदार था, उसके ग्राहकों (customers) को अपने व्यवसाय की ओर आकर्षित करना।

हालाँकि, निवृत्त साझेदार एक समझौता (agreement) कर सकता है कि वह एक निश्चित अवधि (specified period) तक समान व्यवसाय (similar business) या गतिविधि नहीं करेगा।

निर्धारित अवधि के बाद, वह समान व्यवसाय करने या उसका प्रचार (advertise) करने के लिए स्वतंत्र होता है।

Liabilities of outgoing partner to subsequent profits [\(Section 37\)](#)

When the any of the partners ceases to be a partner or dies and remaining partner continues with the business without settling the accounts then the outgoing partner is liable to get a share from the profit earned by the firm since the date he ceases to be a partner.

The share may be attributable to the use of a share of his property or 6% interest per annum on the amount of share in his property.

The surviving partner has the option to purchase the share of the deceased partner and if they purchase it then the deceased partner has no right to get the profit derived from such property.

निवृत्त साझेदार के बाद के लाभ में देयता – धारा 37:

जब कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है और शेष साझेदार उसके खाते का निपटान (settlement of accounts) किए बिना व्यवसाय जारी रखते हैं, तो निवृत्त या मृत साझेदार उस तिथि से प्राप्त लाभ (profits) में हिस्सेदारी पाने का अधिकारी होता है, जिस दिन वह साझेदार नहीं रहा।

यह हिस्सा निम्न में से किसी एक आधार पर हो सकता है—

- उसकी संपत्ति (property) के उपयोग से अर्जित लाभ में हिस्सा, या
- उसकी हिस्सेदारी की राशि पर प्रति वर्ष 6% ब्याज (interest)।

शेष (surviving) साझेदारों के पास यह विकल्प होता है कि वे मृत साझेदार की हिस्सेदारी (share) को खरीद लें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं, तो मृत साझेदार को उस संपत्ति से प्राप्त लाभ में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

Dissolution of a firm

Section 39 to 44 deals with the Dissolution of a firm.

Sometimes circumstances arise when the firm gets dissolved. Sometimes a firm is dissolved voluntary or by the order from the court. There are various modes prescribed under Section 39 to 44 for the dissolution of a partnership firm. Even when the partnership is dissolved then it gives certain rights and liabilities to the partners.

फर्म का विघटन (Dissolution of a Firm):

धारा 39 से 44 में फर्म के विघटन (dissolution) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म का विघटन स्वेच्छा (voluntarily) से भी हो सकता है या न्यायालय (court) के आदेश द्वारा भी किया जा सकता है।

धारा 39 से 44 के अंतर्गत साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीके (modes) निर्धारित किए गए हैं।

साझेदारी के विघटन के बाद भी साझेदारों के कुछ अधिकार (rights) और देयताएँ (liabilities) बनी रहती हैं।

Liability of partners in Different Situations

Liabilities of partners after the dissolution of the partnership firm ([Section 45](#))

The partners are liable for the acts of the firm to the third party until public notice is given. A partner who is declared as insolvent, or who is retired, the estate of a person who dies, or who was not known as a partner at the time of dealing with the third party will not be liable for the act.

विभिन्न परिस्थितियों में साझेदारों की देयता (Liability of Partners in Different Situations):

फर्म के विघटन के बाद साझेदारों की देयता – धारा 45:

साझेदार, फर्म के विघटन (dissolution) के बाद भी तीसरे पक्ष (third party) के प्रति फर्म के कार्यों के लिए तब तक उत्तरदायी रहते हैं, जब तक कि विघटन की सार्वजनिक सूचना (public notice) नहीं दी जाती

हालाँकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में देयता नहीं होती—

- जो साझेदार दिवालिया (insolvent) घोषित हो चुका हो
- जो साझेदार सेवानिवृत्त (retired) हो चुका हो
- मृत व्यक्ति (deceased partner) की संपत्ति (estate)।
- वह व्यक्ति जिसे तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन के समय साझेदार के रूप में जाना ही नहीं गया था।

Wind up the Business Post-Dissolution ([Section 46](#))

When the firm is dissolved every partner has a right to apply for the firm's property in the payment of debts and liabilities. If there is any surplus it needs to be distributed among the partners.

The partners have mutual obligations and rights until the affairs of the firm is wound up.

विघटन के बाद व्यवसाय का समापन (Winding up) – धारा 46:

जब फर्म का विघटन (dissolution) हो जाता है, तो प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि फर्म की संपत्ति (property) का उपयोग पहले उसके ऋणों (debts) और दायित्वों (liabilities) के भुगतान में किया जाए।

यदि सभी देनदारियों का भुगतान करने के बाद कोई अधिशेष (surplus) बचता है, तो उसे साझेदारों के बीच बाँट दिया जाता है।

फर्म के कार्यों के पूर्ण समापन (winding up) तक साझेदारों के बीच पारस्परिक अधिकार (mutual rights) और कर्तव्य (obligations) बने रहते हैं।

Settlement of partnership account ([Section 48](#))

When the partnership has dissolved the accounts of the partners needs to be settled under the usual course of business. Various modes can be used for the settlement of accounts.

If there is a deficiency in capital or loss is incurred when it is paid out of profit. If profit is not sufficient or no profit is earned then it is paid out by the capital and by the partners if necessary. The partners contribute to the proportion of the profit sharing ratio.

The asset of the firm and the capital contributed by the partners to meet up the deficiency in the capital is applied in the following order:

- Repayment to third parties
- The amount which is due to him from the capital
- The amount which is due to him on account of capital
- And if any amount is left then it is distributed among all the partners in their profit sharing ratio.
- **साझेदारी खातों का निपटान (Settlement of Partnership Accounts) – धारा 48:**
- जब साझेदारी फर्म का विघटन (dissolution) हो जाता है, तो साझेदारों के खातों (accounts) का निपटान सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया (usual course of business) के अनुसार किया जाता है। इसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं।
- यदि पूँजी (capital) में कमी (deficiency) या हानि (loss) होती है, तो पहले उसे लाभ (profits) से पूरा किया जाता है। यदि लाभ पर्याप्त नहीं है या कोई लाभ नहीं हुआ है, तो उसे पूँजी से और आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। साझेदार इस हानि को अपने लाभ-वितरण अनुपात (profit-sharing ratio) के अनुसार वहन करते हैं।
- फर्म की संपत्ति (assets) तथा साझेदारों द्वारा दी गई पूँजी का उपयोग निम्नलिखित क्रम (order) में किया जाता है—
 - सबसे पहले तीसरे पक्ष (third parties) के ऋणों का भुगतान।
 - इसके बाद साझेदारों को दिए गए ऋण (loans) की वापसी।
 - फिर साझेदारों की पूँजी (capital) की वापसी।
 - और यदि इसके बाद कोई शेष राशि (surplus) बचती है, तो उसे साझेदारों में उनके लाभ-वितरण अनुपात के अनुसार बाँट दिया जाता है।

Paying Firm Debts and

Separate Debts ([Section 49](#))

In a case when there are joint debts from the firm and the separate debts from the partner then joint debts from the firm is given priority and if any surplus is left then separate debts from the partner is to be paid off.

The property of the individual partners is applied firstly for the payment of separate debts.

फर्म के ऋण और व्यक्तिगत ऋण का भुगतान – धारा 49:

जब फर्म के संयुक्त ऋण (joint debts) और साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण (separate debts) दोनों मौजूद हों, तो सबसे पहले फर्म के संयुक्त ऋणों का भुगतान किया जाता है।

यदि इसके बाद कोई अधिशेष (surplus) बचता है, तो उसका उपयोग साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान में किया जाता है।

इसी प्रकार, साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति (personal property) का उपयोग सबसे पहले उनके व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है।

Personal Profit Earned After Dissolution of Firm ([Section 50 and Section 53](#))

When the firm is dissolved by the death of the partner and business is carried out by the existing partners or his legal heirs then they have to account for the personal benefit earned before winding up the partnership.

Section 53 states that if there is no contract the partner can restrain other partners from carrying similar activities, or using the firm's name or firm's property for their own benefit until the winding up process is complete.

फर्म के विघटन के बाद अर्जित व्यक्तिगत लाभ – धारा 50 तथा धारा 53:

जब किसी साझेदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाता है और शेष साझेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारी (legal heirs) व्यवसाय को जारी रखते हैं, तो उन्हें साझेदारी के समापन (winding up) से पहले अर्जित किए गए व्यक्तिगत लाभ (personal profit) का हिसाब देना होता है।

धारा 53 के अनुसार, यदि कोई विपरीत अनुबंध (contract) न हो, तो प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि वह अन्य साझेदारों को—

- समान व्यवसाय (similar business) करने से,
 - फर्म के नाम (firm's name) का उपयोग करने से,
 - या फर्म की संपत्ति (property) का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से—
- रोक सके, जब तक कि फर्म के कार्यों का पूर्ण समापन (winding up) नहीं हो जाता।

Return of Premium on the Premature Dissolution of the firm (Section 51)

When the firm is dissolved before the expiry of a fixed period, then a partner paying a premium can receive a return of a reasonable part of the premium. Such rules are not applicable in a case when the partnership is dissolved by:

फर्म के समयपूर्व विघटन पर प्रीमियम की वापसी – धारा 51:

जब किसी फर्म का विघटन (dissolution) निर्धारित अवधि (fixed period) की समाप्ति से पहले हो जाता है, तो वह साझेदार जिसने प्रीमियम (premium) का भुगतान किया था, उसे प्रीमियम का उचित (reasonable) भाग वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है।

हालाँकि, यह नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होता जब साझेदारी का विघटन होता है—

Misconduct of partner paying a premium (Section 52)

Post an agreement in which there is no clause for return of premium.

प्रीमियम देने वाले साझेदार का दुराचार (Misconduct of Partner Paying Premium) – धारा 52:

यदि किसी साझेदार ने प्रीमियम (premium) का भुगतान किया है और साझेदारी का विघटन उसके स्वयं के दुराचार (misconduct) के कारण होता है, तो उसे प्रीमियम की वापसी का अधिकार नहीं होता।

इसी प्रकार, यदि साझेदारी के समझौते (agreement) में प्रीमियम की वापसी के संबंध में कोई प्रावधान (clause) नहीं है, तो भी प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा।

Contract Rescinded for Fraud or Misrepresentation

When the partnership arising from the contract is rescinded due to fraud and misrepresentation then the party who has rescinded the contract will be liable as:

After the debt of the firm is paid the lien on remaining assets. He will be treated as a creditor for the payment of any debts made by him.

An indemnity from the partners guilty of misrepresentation or fraud against all debts of firms.

धोखाधड़ी या मिथ्या प्रतिपादन के कारण अनुबंध का निरसन
(Contract Rescinded for Fraud or Misrepresentation):

जब साझेदारी का अनुबंध (contract) धोखाधड़ी (fraud) या मिथ्या प्रतिपादन (misrepresentation) के कारण निरस्त (rescinded) कर दिया जाता है, तो जिस पक्ष ने अनुबंध को निरस्त किया है, उसके निम्नलिखित अधिकार होते हैं—

- फर्म के सभी ऋण (debts) चुकाने के बाद शेष संपत्ति (remaining assets) पर उसका ग्रहणाधिकार (lien) होता है।
- उसके द्वारा दिए गए ऋणों (debts/advances) की वसूली के लिए उसे एक ऋणदाता (creditor) के रूप में माना जाएगा।
- वह उन साझेदारों से क्षतिपूर्ति (indemnity) प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो धोखाधड़ी या मिथ्या प्रतिपादन के दोषी हैं, फर्म के सभी ऋणों के संबंध में।

Sale of Goodwill After Dissolution of Firm (Section 55)

The goodwill is treated as an asset. The goodwill is included in the assets while settling the account after the dissolution of the firm. The goodwill may be sold separately or with other assets. Once the firm is dissolved and goodwill is sold then any partners can carry on a similar business or advertise a business competing with the buyers of the goodwill. The partners are prohibited from doing the following acts:

- To use the name of the firm
- To represent himself as carrying the business
- To solicit the customers of the firm dealing before dissolution.
- **फर्म के विघटन के बाद गुडविल की बिक्री (Sale of Goodwill) – धारा 55:**
- गुडविल (goodwill) को फर्म की संपत्ति (asset) माना जाता है। फर्म के विघटन के बाद खातों के निपटान (settlement of accounts) के समय गुडविल को संपत्ति में शामिल किया जाता है।
- गुडविल को अलग से या अन्य संपत्तियों के साथ बेचा जा सकता है।
- फर्म के विघटन और गुडविल की बिक्री के बाद, कोई भी साझेदार समान व्यवसाय (similar business) कर सकता है या उस गुडविल के खरीदार (buyer) से प्रतिस्पर्धा (competition) कर सकता है।

- किन्तु साझेदारों को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है—
- फर्म के नाम (name of the firm) का उपयोग करना।
- स्वयं को उसी व्यवसाय का संचालक (carrying on the same business) बताना।
- विघटन से पहले के ग्राहकों (customers) को अपनी ओर आकर्षित (solicit) करना।

Conclusion

Partnership is a very common type of business which is prevailing in the country. It has many advantages for the company. This Act is a complete Act as it covers all the aspect related to the partnership.

निष्कर्ष (Conclusion):

साझेदारी (Partnership) एक अत्यंत सामान्य प्रकार का व्यवसाय है, जो देश में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह व्यवसाय के लिए कई लाभ प्रदान करता है।

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 एक व्यापक (comprehensive) अधिनियम है, क्योंकि यह साझेदारी से संबंधित लगभग सभी पहलुओं (aspects) को समाहित करता है।

*****=====*****